रक्षा मन्त्रालय द्वारा सामाजिक संस्थाओं आदि को जीपों, ट्रकों आदि का दिया जाना

4215. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रक्षा मंत्रालय ने जनवरी, 1974 से मई, 1977 तक किन-किन सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों एवं अस्पतालों को रियायती दरों पर कितने ट्रक, जीप, क्रेन एवं स्क्रैप (बुरादे का चूरा) दिए है; और

(ख) क्या सरकार ने इन संस्थाओं को कोटा देते समय उनके सही काम करने के संबंध में संस्था की पासबुक, रसीदें और सदस्यों के रजिस्टरों की जांच की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ट्रक और क्रेन रियायती दरों पर नहीं दिए जाते है और जीप भी हरेक मामले में, रियायती दर पर एक ही दी जाती है । स्क्रैप भी रियायती दर पर जारी की जाती है ।

जिन सामाजिक सगठनों, स्कूलों और अस्पतालों को जनवरी 1974 से मई 1977 की अवधि के दौरान रियायती दरों पर जीपों और स्क्रैप दिए गए है, उनके नाम सभा पटल पर रख गये विवरण में दिए गए है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या 777/77]

(ख) सरकार ने कल्याणकारी/धर्मार्थ/शैक्षणिक संगठनों को फालतू रक्षा स्टोर के आवंट के लिए विस्तृत अनुदेश निर्धारित किए है जिनके अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, इन संगठनों की सदस्यता और उनकी आवश्यकताओं के औचित्य के बारे में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है । उन अनुदेशों में यह भी निर्धारित है कि इन संस्थाओं के तुलन-पत्र और लेखों की जांच कर लेने के पश्चात् उनकी वित्तीय स्थिति का इन प्रमाण-पत्रों में विशेषतौर से जिक्र होना चाहिए । तथापि, प्रसिद्ध शैक्षणिक कल्याणकारी और धर्मार्थ संस्थाओं के बारे में इस प्रक्रिया के अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाता है संलग्न विवरण में जिन संस्थाओं के नाम दिए गए है उनको आवंटन इन अनुदेशों के अनुसार ही किया गया है ?

Small scale industries in Orissa

4216. SHRI D. AMAT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) steps proposed to be taken to set up small scale industries in the backward areas of Orissa;

(b) whether any facilities have been offered by the Government to industrialists to set up industries in the State of Orissa in backward areas; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c). In order to promote the setting up of small scale industries in the backward areas of Orissa the units in the backward districts are given a number of facilities/incentives which include financial assistance on concessional terms by public sector financial institutions under the IDB's Refinance Scheme. The financial concessions are given in the form of lower rate of interest, longer financial grace period, etc. The entrepreneurs in the backward areas enjoy the deduction of 20 per cent from profits and gains for assessing income-tax; machines are supplied on hire purchase basis at concessional earnest money at 10 per cent of the value of machinery to small units by National Small Industries Corporation. NSIC's rate of in-